सेंसेक्स में अब तक 4 कंपनियों का दबदबा

सेंसेक्स में कुछ पुरानी कंपनियों की जगह नई कंपनियां भी लेती हैं

दिग्गज कंपनियों का उतार चढ़ाव बाजार को प्रभावित करता है

नयी दिल्ली, 04 जनवरी. बीएसई के सबसे प्रमुख सूचकांक और देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहे जाने वाले सेंसेक्स के 40 साल के इतिहास में महज चार कंपनियां ही ऐसी हैं जो शुरू से अब तक लगातार इसका हिस्सा रही हैं.

सेंसेक्स में कुल 30 कंपनियां होती हैं. ये बड़ी बाजार पूंजी वाली दिग्गज कंपनियां हैं जिनमें थोड़ा भी उतार-चढ़ाव पूरे बाजार की धारणा को प्रभावित करने की क्षमता रखता है. सेंसेक्स में कभी-कभी कुछ पुरानी कंपनियों की जगह नयी कंपनियों को भी ले लेती हैं. इस साल दो जनवरी को 40 साल पूरे करने वाले सेंसेक्स में चार कंपनियां ही ऐसी हैं जो इसकी शुरुआत से अब तक सूचकांक का हिस्सा रही हैं.

ये कंपनियां हैं - हिंदुस्तान यूनीलिवर, लार्सन एंड टूब्रो, आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज. पहले सेंसेक्स में कौन सी कंपनी शामिल होगी यह उनके कुल बाजार पूंजीकरण पर निर्भर करता था. यह क्रम अगस्त 2003 तक चलता रहा. सितंबर 2003 से यह कंपनी के मुक्त (फ्री-फ्लोट) बाजार पूंजीकरण के आधार पर तय किया जाने लगा. मुक्त बाजार पूंजीकरण की गणना में सिर्फ उन्हीं शेयरों को शामिल किया जाता है जो बाजार में कारोबार के लिए उपलब्ध हैं. इसमें प्रवर्तकों और इनसाइडरों के शेयरों तथा प्रतिबंधित शेयरों को शामिल नहीं किया जाता है.

आईसीआईसीआई बैंक 10.13 प्रतिशत और रिलायंस इंडस्ट्रीज 9.72 प्रतिशत के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. सेंसेक्स में इंफोसिस और भारती एयरटेल का भारांश भी पांच प्रतिशत से अधिक है. शीर्ष 10 कंपनियों का कुल भारांश 65 प्रतिशत है. अपने 40 साल के सफर में सेंसेक्स ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. बीएसई द्वारा जारी श्वेत पत्र के अनुसार, सेंसेक्स के लिए पांच सबसे अच्छे साल 1988, 1991, 1999, 2003 और 2009 रहे हैं. वहीं, पांच सबसे बुरे साल 1995, 1998, 2000, 2008 और 2011 रहे हैं.

> जब दो जनवरी 1986 को सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी उस समय इसमें एसीसी, एशियन केबल्स, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, बॉम्बे बुमराह, बॉम्बे डाइंग, सिएट टायर्स, सेंचुरी एसपीजी., क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ग्लेक्सो स्मिथक्लाइन फार्माशूटिकल्स, ग्रासिम, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स, हिंडाल्को, हिंदुस्तान मोटर्स, इंडियन होटल्स, इंडियन ऑर्गेनिक केमिकल्स (अब फ्यूचुरा पॉलिस्टर्स), इंडियन रेयॉन एंड इंडस्ट्रीज (अब आदित्य बिरला नुवो), आईटीसी लिमिटेड, किर्लोस्कर कमिन्स (अब कमिन्स इंडिया लिमिटेड), एलएंडटी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मुकंद आयरन, नेस्ले, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सिंधिया, सिमेंस, टाटा इंजीनियरिंग शामिल थीं.

बढ़े सोने-चांदी के दाम, निवेशक सतर्क

24 कैरेट सोना 1,35,970 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड 1,24,650 रुपये प्रति 10 ग्राम

अंतरराष्ट्रीय बाजार और आपूर्ति का असर

चीन के निर्यात नियंत्रण से कीमतों में बढ़ोतरी

नई दिल्ली, 4 जनवरी. देश में सोने और चांदी की कीमतों में नए साल की शुरुआत में तेजी देखी जा रही है. बीते एक सप्ताह में 24 कैरेट सोना 750-760 रुपये और चांदी 3,100 रुपये तक महंगी हुई है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में सोना नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार और वैश्विक आपूर्ति में बदलाव के चलते निवेशक और ज्वेलरी खरीदार इस समय सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों पर नजर बनाए हुए हैं. देश में सोने और चांदी के दाम नए साल की शुरुआत में जबरदस्त उछाल के साथ बढ़े हैं. बीते एक सप्ताह के दौरान 24 कैरेट सोना 750-760 रुपये और 22 कैरेट सोना 760 रुपये महंगा हुआ है. दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,35,970 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,24,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी 22 कैरेट गोल्ड का भाव 1,24,500 रुपये और 24 कैरेट का 1,35,820 रुपये दर्ज किया गया. एक सप्ताह में चांदी के दाम 3,100 रुपये बढ़कर 2,41,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए हैं.

निवेशकों की सोना-चांदी के रुझान पर नजर

निवेशकों और ज्वेलरी खरीदारों के लिए यह बढ़ोतरी खास मायने रखती है. अंतराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,392.94 डॉलर प्रति औंस और चांदी का भाव 74.52 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. विशेषज्ञों के अनुसार, चीन द्वारा चांदी के निर्यात पर नियंत्रण और वैश्विक आपूर्ति में असर से भाव आगे भी मजबूत रह सकते हैं. 2025 में सोने ने 73 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की थी और 2026 में भी इसकी मजबूती के संकेत दिख रहे हैं. निवेशक इस समय सोने-चांदी के रुझान पर नज़र बनाए हुए हैं, जबकि ज्वेलरी खरीदार बाजार की बढ़ती कीमतों के बीच अपने निवेश का निर्णय सोच-समझकर कर रहे हैं.

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जल्द

नई दिल्ली, 4 जनवरी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर है. केंद्र सरकार जल्द ही योजना की 22वीं किस्त जारी कर सकती है. हालांकि, इस बार भी सिर्फ उन्हीं किसानों के खातों में पैसा पहुंचेगा, जिन्होंने समय रहते जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं.

अगर आपने ई -केवाईसी, आधार-बैंक लिंकिंग या भू-सत्यापन नहीं कराया है, तो आपकी किस्त अटक सकती है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को जल्द ही 22वीं किस्त मिलने की उम्मीद है. केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है.

अब तक सरकार 21 किस्तें जारी कर चुकी है और अब किसानों को अगली किस्त का इंतजार है. एक रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है, हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. इस बार भी वही किसान योजना का लाभ ले पाएंगे, जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट और सही होगा.

योजना के तहत ई-केवाईसी कराना जरूरी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पीएम किसान योजना के तहत ई -केवाईसी कराना अनिवार्य है. जिन किसानों ने अब तक ई -केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा. किसान यह प्रक्रिया पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर पूरी कर सकते हैं. इसके अलावा आधार-बैंक खाता लिंकिंग भी जरूरी शर्त है. जिन किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, या जिनके खाते में नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी में गड़बड़ी है, उनकी किस्त रोकी जा सकती है. साथ ही बैंक खाते में डीबीटी का सक्रिय होना भी जरूरी है. सरकार ने भू-सत्यापन को भी अनिवार्य किया है. जिन किसानों ने पंजीकरण के समय गलत जानकारी दी थी या जिनका भूमि रिकॉर्ड सत्यापित नहीं है, उन्हें समय रहते सुधार कराना चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसान समय पर ये जरूरी कार्य पूरे कर लेते हैं, तो उन्हें 22वीं किस्त बिना किसी रुकावट के मिल जाएगी.

सब्सक्राइबर और ब्रॉडबैंड ग्रोथ में जियो सबसे आगे

टीआरएआई डेटा पर एनालिस्ट रिपोर्ट्स में जियो की लीड बरकरार

नई दिल्ली, 04 दिसंबर. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हालिया जारी सब्सक्रिप्शन आंकड़ों पर अपनी राय जाहिर करते हुए देश दुनिया के एनालिस्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी रिपोर्ट्स में रिलायंस जियो को फिर से अव्वल बताया है.

ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर में जियो ने कुल वायरलेस सब्सक्राइबर जोड़ने और एक्टिव यूज़र्स की तादाद में बढ़ोतरी के साथ, इंडस्ट्री में शीर्ष स्थान हासिल किया है. जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली और कोटक जैसे एनालिस्टों के अनुसार, जियो ने नवंबर 2025 में करीब 12 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े, जिससे वह लगातार नौवें महीने भारती एयरटेल से आगे बना रहा. खास बात यह रही कि नवंबर में एकमात्र टेलीकॉम कंपनी जियो रही, जिसके एक्टिव सब्सक्राइबर बढ़े, जबकि अन्य कंपनियों को इस मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ा.

देश के 22 में से 17 टेलीकॉम सर्किल्स में जियो का वीएलआर शेयर बढ़ा. जम्मू-कश्मीर और पंजाब में जियो की ग्रोथ सबसे ज्यादा दर्ज की गई.

एनालिस्टों के विश्लेषण के अनुसार, नवंबर में जियो का एक्टिव वीएलआर मार्केट शेयर बढ़कर 43.7त्न हो गया, जो महीने-दर-महीने 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़त दिखाता है. वहीं, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अन्य ऑपरेटर्स के मार्केट शेयर में इस दौरान मामूली गिरावट देखी गई.

> वीएलआर को टेलीकॉम कंपनियों के एआरपीयू से जोड़ कर देखा जाता है. होम ब्रॉडबैंड सेगमेंट में भी जियो की बढ़त बरकरार रही. कोटक की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर में कुल ब्रॉडबैंड नेट ऐडिशन का लगभग 68त्न हिस्सा जियो के नाम रहा. मोबाइल ब्रॉडबैंड और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस दोनों में जियो ने एयरटेल पर बढ़त बनाए रखी. मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक, 5जी एफडब्लूए और यूबीआर सहित फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस में जियो ने एयरटेल के मुकाबले लगभग ढाई गुना अधिक नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं.

ईवी का मोहभंग, लग्जरी में पारंपरिक वापसी

नई दिल्ली, 04 जनवरी. देश में जीएसटी 2.0 बदलावों का असर लग्जरी कार मार्केट पर साफ दिख रहा है. इंडस्ट्री सूत्रों के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री में 2-3 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि पारंपरिक इंजन वाली गाड़ियों की मांग बढ़ रही है. मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी कंपनियों का कहना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और संचालन लागत के कारण ग्राहक अब पारंपरिक इंजन की ओर लौट रहे हैं. देश में लग्जरी कार खरीदारों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का आकर्षण कम होता जा रहा है. ऑटो इंडस्ट्री के एक जारी रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद ईवी की बिक्री में 2-3 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है.

शीर्ष 10 में से सात कंपनियों का पूंजीकरण 1,23,724 करोड़

मुंबई, 04 जनवरी. शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह रही तेजी के बीच बीएसई की शीर्ष 10 में से सात कंपनियों का सम्मिलित बाजार पूंजीकरण (एमकैप) 1,23,724 करोड़ रुपये बढ़ गया जबकि अन्य तीन का कुल बाजार पूंजीकरण 22,623 करोड़ रुपये कम हुआ.

विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का एमकैप सबसे ज्यादा 45,266.12 करोड़ रुपये बढ़कर 21,54,979 करोड़ रुपये हो गया. इस मामले में वह शीर्ष पर रहा. भारतीय स्टेट बैंक का बाजार पूंजीकरण 30,415 करोड़ रुपये और इंजीनियरिंग एवं निर्माण क्षेत्र की कंपनी एलएंडटी का 16,204 करोड़ रुपये बढ़ा. एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनीलिवर के एमकैप में 14,626 करोड़ रुपये और एचडीएफसी बैंक में 13,538 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई. आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 3,104 करोड़ रुपये और दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल का 570 करोड़ रुपये बढ़ा. टीसीएस का एमकैप 10,745 करोड़ रुपये घट गया.

गेहूं मजबूत, दालों में गिरावट

नई दिल्ली, 04 जनवरी. घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव घट गये जबकि गेहूं में तेजी रही. चीनी, दालों और खाद्य तेलों में भी नरमी रही. सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 21 रुपये टूटकर सप्ताहांत पर 3,808 रुपये प्रति क्विंटल रहा. गेहूं पांच रुपये मजबूत हुआ और सप्ताहांत पर 2,863 रुपये प्रति क्विंटल रहा.

आटा चार रुपये महंगा हुआ और 3,315 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया. बीते सप्ताह खाद्य तेलों में गिरावट रही. वनस्पति 125 रुपये और सरसों तेल 103 रुपये प्रति क्विंटल फिसल गया. मूंगफली तेल की कीमत 86 रुपये और पाम ऑयल की 52 रुपये प्रति क्विंटल घट गयी. सोया तेल के दाम 41 रुपये और सूरजमुखी तेल के 10 रुपये प्रति क्विंटल गिर गये. सप्ताह के दौरान मूंग दाल में 68 रुपये और तुअर दाल में 61 रुपये प्रति क्विंटल की नरमी रही. उड़द दाल का भाव 52 रुपये और मसूर दाल का 40 रुपये प्रति क्विंटल टूट गया. चना दाल 29 रुपये प्रति क्विंटल फिसल गयी. मीठे के बाजार में सप्ताह के दौरान गुड़ के औसत भाव 62 रुपये प्रति क्विंटल घट गये. चीनी के भाव भी 17 रुपये प्रति क्विंटल टूट गये.

वैश्विक कारकों से तय होगी बाजार की दिशा

मुंबई, 04 जनवरी. घरेलू शेयर बाजारों में बीते सप्ताह रही तेजी के बाद आने वाले सप्ताह में निवेशकों की नजर घरेलू आंकड़ों के साथ वैश्विक कारकों पर रहेगी. घरेलू स्तर पर सेवा क्षेत्र के पीएमआई के आंकड़े 06 जनवरी को जारी किये जायेंगे. साथ ही वाहनों की खुदरा बिक्री के आंकड़े भी इसी सप्ताह जारी होंगे. बाजार पर सबसे ज्यादा असर वैश्विक कारकों का दिखेगा. इस बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इक्विटी बाजार में लगातार बिकवाल बने हुए हैं, लेकिन घरेलू निवेशक बाजार को गति दे रहे हैं. बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 720.56 अंक (0.85 प्रतिशत) की बढ़त में सप्ताहांत पर 85,762.01 अंक पर बंद हुआ. यह इसका दूसरा सर्वकालिक उच्च स्तर है.

एफपीआई ने बेची 7,608 करोड़ की इक्विटी

म्यूचुअल फंड में उनका शुद्ध निवेश 22 .46 करोड़ रुपये रहा

मुंबई, 04 जनवरी. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने नये साल में पहले दो दिन के कारोबार में भारतीय बाजारों में 7,608 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने जनवरी के पहले दो दिन में भारतीय पूंजी बाजार से 5,342 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की. शुद्ध निकासी का मतलब है कि उन्होंने जितनी पूंजी लगायी उससे ज्यादा निकाली है. एक तरफ जहां एफपीआई इक्विटी से पैसा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे डेट और म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ा रहे हैं. आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने जनवरी में इक्विटी में 7,608 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की. वहीं उन्होंने शुद्ध रूप से 2,266 करोड़ रुपये लगाये. म्यूचुअल फंड में उनका शुद्ध निवेश 22.46 करोड़ रुपये रहा. इक्विटी की तरह ही हाइब्रिड उपकरणों से उन्होंने 22.4 करोड़ रुपये निकाले. उल्लेखनीय है कि कैलेंडर वर्ष 2025 में एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार से 83,972 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की थी. इस दौरान उन्होंने शुद्ध रूप से 1,60,103 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची थी जबकि डेट और म्यूचुअल फंड में उनका निवेश सकारात्मक रहा था. एफपीआई की बिकवाली का एक कारण डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट को भी माना जा रहा है. जब किसी देश की मुद्रा गिरती है तो विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना आम बात है. रुपया इस समय 90 प्रति डॉलर से नीचे है. मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में यह पांच प्रतिशत से ज्यादा लुढ़क चुका है. यही कारण है कि एफपीआई लगातार बिकवाल बने हुए हैं.

समाचार विशेष

विजय को मिल गए 'तुरुप के इक्के'

तमिलनाडु में चुपचाप आकार ले रहा नया गठबंधन

चेन्नई. तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और फिलहाल राज्य में डीएमके गठबंधन की सरकार है. इस बीच राज्य की राजनीति में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है. जहां आमतौर पर तमिलनाडु में गठबंधन अचानक टूटते और बनते रहते हैं, वहीं इस बार एक नया राजनीतिक गठजोड़ धीरे-धीरे आकार लेता दिख रहा है. बीते कुछ हफ्तों में अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) ने राज्य के दो हाशिये पर चले गए बड़े राजनीतिक चेहरों से संपर्क बढ़ाया है. ये नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और अम्मा मक्कल मुनेत्र कज़गम (एएमएमके) के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन.

अगर ये दोनों पूर्व अन्ना द्रमुक (एआईएडीएमके) नेता टीवीके में शामिल होते हैं, तो यह पार्टी के लिए अब तक का सबसे अहम राजनीतिक जुड़ाव माना जाएगा. इससे 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले टीवीके को एक गंभीर राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में पहचान मिल सकती है. टीवीके और एएमएमके के कई वरिष्ठ नेताओं ने इन चर्चाओं की पुष्टि की है. यह बातचीत उस समय तेज हुई है, जब कुछ हफ्ते पहले पूर्व एआईएडीएमके नेता के ए सेंगोत्तैयन टीवीके में शामिल हुए थे, जो पार्टी से जुड़ने वाले पहले बड़े नामों में गिने जाते हैं.

दोनों दलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मुताबिक बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है. एक वरिष्ठ टीवीके नेता ने कहा कि पार्टी की दिशा स्पष्ट है और दोनों नेताओं को साथ लाने में बड़ा राजनीतिक लाभ दिख रहा है. उन्होंने कहा कि ये नेता न सिर्फ अनुभव लाते हैं, बल्कि एक तैयार सामाजिक आधार भी साथ लाते हैं. ओ पन्नीरसेल्वम, जिन्हें ओपीएस के नाम से जाना जाता है, और दिनाकरन दोनों का थेवर समुदाय में खासा प्रभाव है. यह समुदाय दक्षिणी और डेल्टा क्षेत्रों में एक मजबूत ओबीसी समूह माना जाता है. इनके शामिल होने से टीवीके को थेनी, मदुरै, शिवगंगा, रामनाथपुरम और कावेरी डेल्टा के कुछ हिस्सों में संगठनात्मक मजबूती मिल सकती है.

विजय | ओ पन्नीरसेल्वम | टीटीवी दिनाकरन

दिनाकरन और ओपीएस की स्थिति- इन दोनों नेताओं के लिए यह कदम सीमित राजनीतिक विकल्पों का नतीजा भी माना जा रहा है. एक समय एएमएमके ने एआईएडीएमके के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन फिलहाल दिनाकरन खुद राजनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ते नजर आ रहे हैं. उन्होंने तब तक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से गठबंधन से इनकार कर रखा है, जब तक एडप्पादी के पलानीस्वामी मुख्यमंत्री पद का चेहरा बने हुए हैं. वहीं एआईएडीएमके से निष्कासन और बीजेपी-आरएसएस के समर्थन में कमी के बाद ओपीएस के पास भी मजबूत पार्टी ढांचा नहीं बचा है.

सूत्रों के अनुसार अब स्थितियों में बदलाव

खबरों के अनुसार, पन्नीरसेल्वम के सामने दो विकल्प थे, डीएमके और टीवीके. लेकिन डीएमके का विकल्प लगभग बंद हो चुका है. एक वरिष्ठ डीएमके नेता ने सीट बंटवारे और अंदरूनी असंतोष का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी उन्हें समायोजित नहीं कर सकती. बताया जा रहा है कि दिनाकरन ने कम से कम 20 सीटों की मांग रखी थी, जिसे डीएमके स्वीकार नहीं कर सकती. ऐसे में टीवीके ही उनके सामने एकमात्र विकल्प बचा है. हालांकि टीवीके कुछ महीने पहले ही बनी है और अब तक उसका संगठन कमजोर माना जाता रहा है, जो विजय की लोकप्रियता पर काफी निर्भर था. लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अब स्थिति बदल रही है. एक वरिष्ठ टीवीके नेता ने कहा, हम इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते. दिनाकरन और ओपीएस के आने से पार्टी को विश्वसनीयता, अनुभव और दक्षिणी तमिलनाडु में स्पष्ट विस्तार मिलेगा.

हैदराबाद. तेलंगाना में 2023 के अंत में विधानसभा हारने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सक्रिय राजनीति से अलग हो गए थे. बीच में उनकी सेहत भी बिगड़ी थी, जिसकी वजह से वे सार्वजनिक जीवन से दूर रहे.

फिर सक्रिय हो रहे केसीआर

हैदराबाद से बाहर अपने फार्म हाउस में उनका ज्यादा समय बीत रहा था. उनकी ओर से बेटे केटी रामाराव और भतीजे हरीश राव पार्टी का राजनीति संभाल रहे थे. इसी बीच बेटी के कविता का भी विवाद हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता की पार्टी का भाजपा में विलय कराने की साजिश हो रही है. इसके बाद उनको निकाल दिया गया और उन्होंने तेलंगाना जागृति के नाम से पार्टी बनाई है.

बहरहाल, दो साल के बाद के चंद्रशेखर राव ने अपना स्वघोषित वनवास समाप्त किया है. वे अपने फार्म हाउस से निकले और विधानसभा गए. वे वहां मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिले. दोनों ने हाथ मिलाए. कहा जा रहा है कि केसीआर अब राजनीति में सक्रिय होंगे. स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले उनकी सक्रियता से भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाली होगी. सबकी नजर इस पर भी है कि वे अपने परिवार का विवाद कैसे निपटाते हैं.

पवार के लिए राज्यसभा का रास्ता कहां से बनेगा?

मुंबई. अगले साल अप्रैल में महाराष्ट्र में राज्यसभा की सात सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से दो सीट शरद पवार की एनसीपी की है. एक सीट उद्धव ठाकरे की शिव सेना की है और एक सीट कांग्रेस की है. यानी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की चार सीटें हैं. बाकी तीन सीटें महायुति की हैं, जिनमें दो भाजपा की और एक आरपीआई अठावले की है.

विपक्षी गठबंधन की चार सीटों में से एक सीट शरद पवार की है. उनकी पार्टी की फौजिया खान भी रिटायर हो रही हैं. उद्धव ठाकरे की पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस से रजनी पाटिल रिटायर हो रही हैं. अपने दम पर विपक्षी गठबंधन को एक सीट मिल सकती है. उद्धव ठाकरे की कोशिश होगी कि सीट उनके खाते में जाए. वैसे भी उनकी पार्टी के सबसे ज्यादा 20 विधायक हैं. इसी आधार पर उनकी पार्टी ने मुख्य विपक्षी पार्टी का दावा भी किया है. दूसरी ओर आठ एमएलसी के दम पर कांग्रेस ने विधान परिषद में मुख्य विपक्षी दल का दावा किया है.

> जाहिर है तीनों पार्टियां अपनी अपनी संख्या के हिसाब से दावेदारी कर रही हैं. उद्धव ठाकरे के 20, कांग्रेस के 16 और शरद पवार के सिर्फ 10 विधायक हैं. एक सीट जीतने के लिए 35 वोट की जरुरत है. उद्धव और कांग्रेस को मिला कर 36 वोट हैं. यानी वे अपने दम पर एक सीट जीत सकते हैं. विपक्षी गठबंधन को सिर्फ एक ही सीट मिलेगी. बची हुई छह सीटें महायुति के खाते में जाएंगी, जिनमें से तीन सीट भाजपा के लेने की चर्चा है.

विशेष ममता ने निकाल ली कबीर की काट, भाजपाई सियासत की लगेगी वाट?

बाबरी मस्जिद पर भारी पड़ेगा महाकाल मंदिर

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में एक महीने पहले झरूष्ट से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर राज्य में बाबरी मस्जिद बनाने की जोरदार वकालत कर रहे हैं. उनके कामों ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है. हालांकि, ममता बनर्जी ने अब एक नई घोषणा करके कबीर की राजनीतिक चालों को करारा झटका दिया है.

बाबरी मस्जिद के लिए हुमायूं की मांग के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के सबसे बड़े महाकाल मंदिर के बारे में एक बड़ा अपडेट दिया है. सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि राज्य के सबसे बड़े महाकाल मंदिर की नींव जनवरी के दूसरे हफ्ते में रखी जाएगी. उन्होंने यह महत्वपूर्ण घोषणा न्यू टाउन में एक दुर्गा मंदिर की नींव रखते समय की.

ममता के दांव ने मचाई सियासी हलचल- ममता बनर्जी की इस घोषणा के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. हर तरफ से केवल से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी का यह दांव आने वाले बंगाल चुनाव में कामयाब होने वाला है?

क्या ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर के लिए रणनीतिक काट खोज ली है? दरअसल, पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया.

इससे पहले जब उन्होंने यह ऐलान किया था तभी ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक राजनीतिक का हवाला देते हुए कबीर को टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था.

भाजपा ने लगाया ध्रुवीकरण का आरोप

हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी को टारगेट करना शुरू कर दिया. बीजेपी ने आरोप लगाया की तृणमूल कांग्रेस ध्रुवीकरण के लिए इस विधायक का इस्तेमाल कर रही हैं. साथ ही उन्हें चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि वह आग से खेल रही हैं.